P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-1) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारतीय अर्थव्यवस्था मे कृषि की भूमिका का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

टी.आर. रात्रे
सहायक प्राध्यापक,
अर्थ शास्त्र विभाग,
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर, छ.ग., भारत

सारांश

भारत को जनगणना 2011 के अनुसार गांवो का देश कहा जाता है यहॉ कि 67.5% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करती है तथा 62% जनता का आजीविका का प्रमुख साधन कृषि क्षेत्र है जहॉ 54% श्रम शक्ति कार्यरत् है, स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि, औद्योगिक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान कमशः 55%, 24%, एवं 21% था किन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे–जैसे विकास की ओर अग्रसर हुआ वैसे ही वर्तमान में GDP में कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र की योगदान घटकर 18.9% हो गया, उद्योग क्षेत्र का 30 एवं तृतीय क्षेत्र का योगदान 51.5% हो गया उसके बावजूद कृषि क्षेत्र खाद्यान्न की उपलब्धता एवं ग्रमीण क्षेत्र के लिए रोजगार का बड़ा केन्द्र है तथा राष्ट्रीय आय, औद्योगिक विकास, पूंजी निर्माण, रोजगार तथा अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। हम प्रकार भारत जैसे–जैसे विकास कर रहा है, GDP में कृषि क्षेत्र का अंशदान कमशः घटती जा रही है।

मुख्य शब्द : कृषि का महत्व कृषि वृद्वि दरें एवं खाद्यान्न उत्पादन।

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। 1950–51 में कुल कम शक्ति में 70 भाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत था जो कि वर्तमान में घटकर 54.5 प्रतिशत हो गया। भारत के पंचवर्षीय योजना लागू होने से द्वितीय क्षेत्र जैसे उद्योग, विनिर्माण, निर्माण, तथा तृतीयक क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, मुद्रा एवं बैकिंग क्षेत्रों में निवेश बढने में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में अंशदान में कमी आ रही है, ज्यादातर पूंजीपति उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में निवेश में रूचि ले रहे है। कृषि क्षेत्र में ऐसे वर्ग कार्यरत है जैसे सीमांत कृषक, लधु एवं मध्यम कृषक जिनकी आय कम है एवं पूंजी की कमी है, तथा भारत में कृषि क्षेत्र मे सिंचाई 42 प्रतिशत है, जो कि बहुत कम है, मानसून पर निर्भर है तथा प्राकृतिक आपदा आने से कृषि फसलें को काफी नुकसान होता है। उसके बावजूद भारत में कृषि वस्तुऍ का निर्यात बड़ी मात्रा में दुसरे देशों के किया जाता है तथा यह क्षेत्र उद्योग धंधो के लिए कच्चा माल का प्रमुख केन्द्र है, राष्ट्रीय आय, रोजगार, प्रभावपूर्ण मांग, खाद्यान्न उपलब्धता का एक प्रमुख केन्द्र है। भारत मे 1966–67 में हरित क्रांति आने के कारण भारत की प्रमुख फसलो की उत्पादन एवं उत्पारकता मे तेजी से वृद्धि हुई है किन्तु कृषि क्षेत्र की लगातार उपेक्षा होने से निवेश मे कमी आयी है जिससे कृषि वृद्वि दरें घटती जा रही है। जिसके कारण इस क्षेत्र को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो कि भारत जैसे विकासशील देशो के लिए चिंतनीय विषय है।

तालिका 01
साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि का भाग
(वर्ष 2011–12 की कीमतों पर)

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद मे कृषि क्षेत्र का भाग प्रतिशत
1950–51	55.1%
1970–71	44.3%
1990–91	31.4%
2007–08	17.8%
2009–10	14.6%
2015–16	13.9%
2018–19	13.0%

स्रोतः– भारत सरकार आर्थिक समीक्षा 2018–19

उपरोक्त तालिका क्र.–01 से स्पष्ट है कि वर्ष 1950–51 मे जहॉ GDP में 55.1% कृषि क्षेत्र का योगदान था जोकि 2018–19 मे घटकर 13.0 हो गया उसका कारण यह है कि कृषि क्षेत्र मे पूंजी निवेश की कमी रही है।

तालिका 02

विभिन्न पंचवर्षीय योजना मे कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर

योजना	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956)	2.71
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–1961)	3.15
तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–1966)	–0.73
तीन वार्षिक योजनाएँ (1966–1969)	4.16
चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–1974)	2.57
पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–1979)	3.28
छठी पंचवर्षीय योजना (1980–1985)	2.52
सातवी पंचवर्षीय योजना (1985–1990)	3.47
आठवी पंचवर्षीय योजना (1992–1997)	4.72
नौवी पंचवर्षीय योजना (1997–2002)	2.44
दसवी पंचवर्षीय योजना (2002–2007)	2.30
ग्यारहवी पंचवषीय योजना (2007–2012)	3.33
बारहवी पंचवर्षीय योजना (2012–2017)	4.0 (लक्ष्य)

स्रोतः– भारत सरकार आर्थिक समीक्षा 2018–19

उपरोक्त तालिका क0–02 से स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना मे कृषि वृद्रि दर 2.71% था, दुसरी पंचवर्षीय योजना मे बढ़कर 3.15% हो गया किन्तु भारत–चीन युद्ध 1962 मे होने के कारण कृषि क्षेत्र मे पूंजी निवेश नही हुआ और कृषि वृद्रि कर घटकर– 0.73 प्रतिशत हो गया केवल आठवी पंचवर्षीय योजना मे संर्वाधिक 4.72% रही है।

तालिका क्रमांक –03

पिछले कुछ वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन

वर्ष	खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन .टन)
1950–51	51.5
2010–11	244.5
2011–12	259.3
2012–13	257.1
2013–14	265.0
2014–15	252.0
2015–16	251.5
2016–17	273.4
2018–19	281.37
2019–20	285.6 अनुमानित

स्रोत :– भारत सरकार आर्थिक समीक्षा 2018–19

उपरोक्त तालिका क्र.–03 मे स्पष्ट है कि वर्ष 1950–51 मे भारत का कुल खाद्यान्न 51.5 मिलियन टन था जो कि वर्ष 2010–11 मे 244.5 तथा 2018–19 मे बढ़कर 281.37 मिलियन टन हो गया 2019–20 मे बढ़कर 285.6 मिलियन टन अनुमानित किया गया है अर्थात् 69 वर्षों में केवल 5.54 गुना वृद्धि हुई है।

भारत मे कृषि उपज के निम्न उत्पादकता के कारण

1. सिंचाई सुविधायों का अभाव है, वर्तमान मे भारत की सिंचित क्षेत्रफल केवल 42% है कुछ राज्यो जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्यों में 70% मे अधिक सिंचित क्षेत्रफल है, जबकि शेष राज्यो मे राष्ट्रीय औसत से कम है।
2. ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषक अभी भी बड़ी पैमाने मे देशी बीजो का अधिक प्रयोग कर रहें है, जबकि उन्नत, बीज का प्रयोग कुल बोया गया रकबा मे 40% ही है।
3. जोतो के उपविभाजन और विखण्डन की समस्या होने के कारण कृषि क्षेत्र मे यंत्रीकरण नही हो पा रहा है।
4. ग्रामीण कृषको के पास कृषि कार्य के लिए वित्त, साख सुविधाओं की कमी है प्रायः अधिकतर कृषक ऋण ग्रस्त है, समय पर सहकारी संख्थाओं, बैक से पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साख सुविधाएँ नहीं मिल रही है।
5. कृषि क्षेत्रों मे पूंजी निवेश की कमी है, ज्यादातर पूंजीपति कृषि क्षेत्र में रूचि नही लेते है। कृषक वर्ग है जिनके पास आय कम होने के कारण श्रम एवं पूंजी की पर्यप्त मात्रा मे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।
6. देश की बढ़ती हुई आबादी के कारण अधिकतर ग्रामीण श्रमिक, कृषि कार्य में संलग्न है जहॉ पर उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य है।
7. कृषि फसलों का कीमते कम है जिनके कारण कृषि क्षेत्र में आय व रोजगार की अधिक समस्या हो रही है कृषक कृषि उत्पादन पर कम रूचि ले रहे है।
8. कुल कृषि जोतें में 76% सीमांत कृषक है जिनकी आय निम्न है जिसके कारण कृषि क्षेत्र का विकास काफी धीमी है।
9. कृषि क्षेत्र विद्युतीकरण, प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक का उपयोग नही होने के कारण कृषि उत्पादकता मे वृद्रि नही हो पा रही है।

उपाय

1. भारतीय कृषि मे पूंजी निवेश को प्राथमिकता दिया जाय।
2. कृषि क्षेत्र मे सिंचाई सुविधाओं जैसे लघु सिंचाई योजना का विस्तार किया जाना चाहिए।
3. उन्नत बीजो, रासायनिक खादो का अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।
4. आधुनिक कृषि उपकरणो जैसे स्प्रिकलरो, ट्रेक्टर, थ्रेसर, आदि का उपयोग किया जाना चाहिए।
5. मृदा अंरक्षण के लिए मेड़ों को मजबूतीकरण किया जाना चाहिए, घरेलू कम्पोस्ट का उपयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए।
6. ग्रामीण कृषको को सब्सिडी दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अधिकतम उत्पादन कर सके।
7. निम्न ब्याज दर पर कृषि ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

8. कृषि उपज का मूल्य वर्तमान मे धान का 1835 रूपये प्रति क्विंटल है उसे 2500 रूपये किया जाना चाहिए जिसमे कृषक की आय एवं क्रय शक्ति में वृद्धि हो सके।
9. कृषि कार्य के लिए विद्युत पंप की उपलब्धता किया जाना चाहिए जिसमे कि वे खरीफ एवं रबी मौसम मे भी उपयोग किया जा सके जिसमे कि फसलो की उत्पादन एवं उत्पादकता मे वृद्वि हो सके।
10. कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।
11. कृषको को कृषि विज्ञान केन्द्र एवं अन्य प्रशिक्षण संख्याओ के माध्यम मे कृषि कार्य के पद्धति के बारे में अधिक से अधिक प्रषिक्षण दिया जावे।
12. सरकार के बफर स्टॉक के लिए विपणन केन्द्र का विस्तार किया जाना चाहिए।
13. कृषि फसलो की उचित रख–रखाव एवं खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

Gulati, Ashok (1996) "New Economic Policy and Indian Agriculturure- Summary of Discussion" IJAE Jan – June 1996.

Gamble W.K. D.W., Adams and P. Droner (1970) "Discussion; the Green Revolution: The second Generation problems – Institutional Reforms, The conlict between Equity and productivity" IJAE, Dec. 1970.

Rao, C.H.H. (1989) "Technological change in Indian Agriculture: Energing Trends and perspectives "Indian Journal of Agriculture Economics Oct.- Dec. 1989.

Bhalla, G.S. (1974), Changing – Agriculture in India – A study of the Impact of Green Revolution in Haryana Merrut Meenakshi Prakashan.

Mruthy Unjaya and Pradaman Kumar (1989)" Crop Economic and Cropping Pattern changes "EPW. Dec. 21, 1989.

Kalirajan, K.P. and R.T. Shand (1997) source of output growth in Indian Agriculture" IJAE, Oct.- Dec. 1997.